and this year under the non-resident Indian imports scheme; the number of films cleared and released for exhibition;

(b) what are the reasons of delay in clearing the remaining cases; and

(c) what was the objective of this non-resident Indian imports scheme and the extent to which these have been fulfilled?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) Upto 18-8-85, 51 feature films had been cleared by the National Film Development Corporation for import by the non-resident Indians. As per copies of bills of entry submitted by the non-resident Indians, upto 18-8-85, 27 films had actually been imported—all in 1985. As regards release of these films for exhibition, the non-resident Indians are not in all cases required to give information to the Corporation;

(b) The applications of non-resident Indians for import of feature films are cleared expeditiously. In those cases where there is delay, the reasons generally are:

(i) Non-submission of relevant documents required to be sent with the applications; and

(ii)) Non-receipt of a print/video cassette from the applicants in the absence of which the films cannot be pre-viewed.

(c) The main objective of the policy regarding import of films by non-resident Indians is to import good non-MPEAA (Motion Picture Export Association of America) foreign films in larger number, as the National Film Development Corporation can import only a limited number of films due to constraints of foreign exchange. The objective has been fulfiled to some extent. A number of foreign films have already been imported. However, due to absence of the guidelines regarding quality of films to be imported, initially, all the films were not of good quality. Such guidelines have since been notified on 1st July, 1985.

राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्र

2876. **श्री भंवर लाल पंवार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दूरदर्शन सुविधाएं कहां-कहां उपलब्ध है ;

(ख) शेष इलाकों में दूरदर्शन सुविधा कब तक सुलभ करा दी जायेगी ;

(ग) क्या पाली जिले को भी सम्मिलित करते हुए सिरोही जिले में हाई पावर (उच्च क्षमता का) टी०वी० रिले केन्द्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो इसे कब तक लगाया जायेगा;

(घ) क्या सीमावर्ती इलाकों में स्थापित लघु क्षमता के दूरदर्शन केन्द्रों को उच्च क्षमता में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) राजस्थान मे इस समय दूरदर्शन ट्रांसमीटर जयपुर, सूरतगढ़, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर खेतड़ी बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर और बाडमेर में कार्य कर रहे है। दिल्ली आगरा तथा भटिंडा के दूरदर्शन ट्रांसमीटर भी राजस्थान के कुछ भागों को सेवा प्रदान करते हैं।

(ख) राज्य के कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश के कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।